चीनी में घुलने लगी कीमतों में इजाफे की चाशनी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 10 मार्च

वैश्विक बाजार में चल रही प्रवृत्ति और चीनी की अतिरिक्त मात्रा को देश से बाहर भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने की संभावना को देखते हुए स्थानीय बाजारों में चीनी की कीमतें बढ़ सकती हैं।

हालांकि कीमतें चढ़नी शुरू हो चुकी हैं लेकिन वैश्विक बाजार की तुलना में भारत में यह उछाल कम है।

इस कैलेंडर वर्ष में स्थानीय थोक बाजारों में अब तक मात्र 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33.50 रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले, विश्व बाजार में चीनी की कीमतों में 18 प्रतिशत का अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। बेंचमार्क इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर सोमवार को चीनी के दाम प्रति सेंट 14.80 पॉन्ड तक चढ़ चुके थे, जबकि साल की शुरुआत में ये प्रति सेंट 12.67 पॉन्ड ही थे।

चीनी की कीमतों में इजाफे की इस संभावना से पेराई करने वाली उन मिलों को राहत मिलेगी जो पिछले चार सालों से कीमतों के जबरदस्त दबाव में चल रही थीं। छिटपुट उदाहरणों को छोड़कर चीनी की कीमतों में पिछले चार सालों के दौरान उत्पादन लागत से नीचे का रुख रहा है जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों को भारी वित्त संकट से जूझना पड़ा। पिछले कुछ वित्त वर्षों के दौरान अधिकांश मिलों को भारी घाटा सहना पड़ा। चीनी मिलों के इस संकट को समझते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलों को दिवालिया होने से बचाने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। एक बड़ी फर्म के विश्लेषक ने कहा, 'हाल में भारत में चीनी की कीमतों ने वैश्विक प्रवृत्ति का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं लेकिन स्थानीय बाजारों में ये पीछे रही हैं। इसलिए चीनी की कीमतें निश्चित ही स्थानीय बाजारों में बढ़ेंगी।'

दरअसल, पिछले कुछ महीनों में आधारभूत तत्त्वों से इसे सहायता मिलती रही है। वैश्विक बाजार में अत्यधिक आपूर्ति के अनुमान से विश्लेषकों ने विश्व बाजार में 20 लाख टन की कमी का पूर्वानुमान जताया था। कुछ अन्य शोध संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय चीनी संघ जैसी एजेंसियों ने ब्राजील में मौसम की प्रतिकूल दशाओं के कारण वर्ष 2016 में 20-40 लाख टन वैश्विक कमी का पूर्वानुमान जताया था।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, 'इससे चीनी मिलों को इस साल बड़ी मात्रा में चीनी निर्यात करने का मौका मिलेगा जिसके लिए सरकार ने 32 लाख टन की सीमा निर्धारित की है। निर्यात की मात्रा के अनुरूप घरेलू उपलब्धता और आपूर्ति के दबाव में कमी आएगी। चूंकि हमने भारत में चीनी उत्पादन के 2.6 करोड़ टन से नीचे रहने का पूर्वानुमान जताया है, इसलिए घरेलू आपूर्ति दबाव कम करने के लिए निर्यात करना जरूरी है।'